Himalayan J. Soc. Sci. & Humanities ISSN: 0975-9891
Vol. 17, (2022) 85-88 DOI: https://doi.org/10.51220/hjssh.v17i1.13

COVID-19 and Reverse Migration

Chandra Pal

Department of Commerce S.B.S. Govt. P.G. College, Rudrapur (Udham Singh Nagar)

Corresponding Author: cpcommerce1984@gmail.com

Received: 23.07.2022; Revised and Accepted: 28.11.2022
©Society for Himalayan Action Research and Development

Abstract: Due to COVID-19, there has been a limited economic, social, political, religious and cultural activity. It has given rise to many apprehensions about the future. The critical situation of reverse migration too arose from the corona pandemic. While reverse migration has given rise to many other problems, on the other hand they have come to their native village or place and have populated the deserted village and such people are making significant contribution to the economy by adopting local employment, agriculture etc. Due to this their number has increased in schemes like MNREGA. Through this article, the various impacts of COVID-19 on the global level and the problems and challenges arising due to reverse migration are to be shed light.

Keywords: Corona Pandemic, Reverse Migration & Indian Economy

कोविड 19 और प्रतिलोम पलायन

चंद्र पाल

वाणिज्य विभाग, एस० वी ० एस ० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर

सारांश : कोविड 19 के कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ सीमित हो गई हैं। इसने भविष्य को लेकर कई आशंकाओं को जन्म दिया है। रिवर्स पलायन की विकट स्थिति भी कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई। रिवर्स माइग्रेशन ने जहां कई अन्य समस्याओं को जन्म दिया है, वहीं दूसरी ओर वे अपने पैतृक गांव या स्थान पर आ गए हैं और वीरान गांव को आबाद कर चुके हैं और ऐसे लोग स्थानीय रोजगार, कृषि आदि को अपनाकर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इससे मनरेगा जैसी योजनाओं में इनकी संख्या बढ़ी है। इस लेख के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के विभिन्न प्रभावों और रिवर्स माइग्रेशन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालना है।

कूटशब्द– कोरोना महामारी, रिवर्स माइग्रेशन और भारतीय अर्थव्यवस्था

कोविड 19 वैश्विक महामारी की शुरूआज चीन के वुहान शहर से हुई। इससे विश्व में 1930 में आई महामंदी की पुनर्रावृत्ति हो गई है। कोरोना ने जहां आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां को सीमित कर दिया है। वही भविष्य के प्रति आशंकाओं को बल दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि "कोरोना के कारण इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3 फीसदी की गिरावट आएगी।" अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत लंबे समय तक महामारी के साथ काम करना पड़ेगा। यहां के निवासियों को अपनी दिनचर्या में कोरोना को शामिल करके आर्थिक गतिविधियां जारी रखनी होंगी। उदाहरण के लिए भारत में लगभग 50 दिन लॉकडाउन रहा। सरकारों को अधिकतर राजस्व शराब, तम्बाकू, खनन, तेल, रजिस्ट्री आदि से आता है। इस दौरान राज्य सरकारों को हालत इतनी गंभीर हो गई कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए ऋण लेना पड़ा। यहां तक कि अनावश्यक व्ययों, भत्तों पर रोक विधायको उवं सांसदों की निधि को कोरोना मद में समायोजन और सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन से एक दिन की कटौती को सी0एम0 राहत कोष में जमा

करने जैसे अनेक कार्य करने पड़े। कारोना संक्रमण पर अभी तक पूरी तरह रोक नहीं लग पायी है, इसका दूसरा स्ट्रेन आना और टीके का सर्व सुलभ न होना, चिन्ता का विषय बन गया है।

भारत में 25 मार्च 2020 को प्रथम लॉकडाउन हुआ, तभी से प्रवासी एवं दिहाड़ी कामगारों के रोजगार बन्द होने से रिवर्स पलायन की समस्या उत्पन्न तेजी से होने लगी। इसका सबसे बुरा प्रभाव असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाले लोगों पर पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश और बेहतर जीवन जीने के लिए शहरों और महानगरों की ओर जाने की स्थिति को पलायन कहा जाता है। कोविड 19 के समय होने वाला पलायन सामान्य दिनों की तुलना में बिल्कुल विपरीत है। लॉकडाउन के समय असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी श्रमिकों को अपने मूल गांव या स्थान को वापस लौटने की स्थिति को रिवर्स पलायन की संज्ञा दी गई है।

ग्रामीण आबादी के ऐसे लोग जो अपने गांवो में पैतृक कार्य करते हैं। ये लोग मौसमी बेरोजगारी के कारण शहरों और महानगरों की ओर पलायन करते हैं। इनमें से अधिकांश लोग फसल की बुआई एवं कटाई के लिए अपने गांव चले जाते हैं और बाकी समय महानगरों में रहकर दिहाड़ी मजदूर, रसोईया, डिलीवरी बॉय, चपरासी, गार्ड, सहायक आदि का कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। देश में इनकी संख्या लगभग 50 करोड. है जिसका 90 प्रतिशत भाग असंगठित क्षेत्र में काम करता है। कोरोना महामारी ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में रिवर्स पलायन की गंभीर समस्या को उत्पन्न कर दिया है। भारत के अनेक राज्यों के कामगार, दिहाड़ी मजदूर, ठेली वाले एवं छोटे दुकानदार सरकार से अपने गन्तव्य स्थान जाने के लिए सरकार से आस लगाए हुए थे। इसके बावजूद भी लॉकडाउन में कैद, भूख–प्यास से बेहाल और बन्द काम धन्धों ने दिहाड़ी एवं प्रवासी श्रमिकों को अपने गांवों की ओर पैदल, साइकिल तथा रिक्शे से चलने पर मजबूर होना पड़ा। अधिकांश श्रमिक बिना खाए पिए सैकड़ो किलोमीटर पैदल चले, इस दौरान काफी प्रवासी सड़क दुर्घटना के शिकार हुए, गर्भवती महिलाओं ने रास्ते में ही बच्चों को जन्म दिया, तो कुछ भूख–प्यास से मरे। यद्यपि केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने उनसे वहीं रूकने का अनुरोध भी किया। इनके लिए स्पेशल बसों तथा ट्रेनों का प्रबन्ध भी किया लेकिन प्रवासियों की बड़ी संख्या के सामने यह प्रयास बौने साबित हुए। रिवर्स पलायन की समस्या अधिकतर बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिसा, मध्य प्रदेश और झारखण्ड राज्यों में अधिक आयी है।

बिहार में रिवर्स पलायन की शुरूआत 3 मई 2020 से ही हो गई थी। यहां के श्रमिक दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर के रूप सर्वाधिक जाते हैं। अन्य राज्यों में इन मजदूरों को तुलनात्मक रूप से अधिक मजदूरी मिलती है। कोई व्यक्ति अधिक आय कमाने एवं बेहतर भविष्य के लिए पलायन करे तब ये बात समझ में आती है। लेकिन जब लोग पेट की भूख शान्त करने के लिए जायें तो वास्तव में चिन्ता का विषय है। गांवो में 100 दिन के रोजगार की गारण्टी देने वाली मनरेगा, कृषि और वहां स्थापित उद्योग धन्धे होते, तब ऐसी समस्या नहीं आती। कहीं न कहीं ये स्थिति राज्य सरकार की लापरवाही को उजागर करती है।

कामगारों की दशा एवं आर्थिक गतिविधि को जांचने हेतु किए गए निष्कर्ष बताते हैं कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में 40 लाख श्रमिक बेकार हो गए। यह 19.5 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा और सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत के प्रति तिमाही 12 अरब डॉलर से अधिक का इजाफा होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 के अनुसार देश में 1991–2001 के दशक में पलायन की दर 2.4 प्रतिशत थी जो 2001–2011 के दशक में लगभग 2 गुनी बढ़कर 4.5 प्रतिशत तक पहुंच गई। उत्तराखण्ड के आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 में कहा गया है कि कृषि में गिरावट, लगातार गिरती आय और तनावग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण यहां पलायन अधिक हुआ। प्रारम्भ से ही उत्तराखण्ड में पलायन बहुत गंभीर समस्या के रूप में रहा है। इस कारण से यहां के कई गांव खाली होकर भुतहा गांव बन गए। इन गांवो में अब कोई नहीं रहता। सितम्बर 2020 में प्रकाशित उत्तराखण्ड ग्राम्य एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लॉकडाउन के कारण 357536 प्रवासी घर वापस लौटे। पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में रिवर्स पलायन के कारण सर्वाधिक लोग वापस लौटे।

रिवर्स पलायन से उत्पन्न समस्याएं–

1. असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर आर्थिक संकट– रोजगार और भुखमरी ने इनके सामने आर्थिक संकट ला दिया। आंकड़े बताते हैं कुल 26.2 करोड़ गैर कृषि श्रमिकों में से 14 करोड़ से अधिक मजदूर, रोजगार बन्द होने से बेकार हो गए। रिवर्स पलायन के कारण मूल गांव मे आकर इनके सामने रोजी–रोटी का संकट पैदा हो गया।

2. कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए श्रमिकों का अभाव– पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि कार्यों हेतु बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। रिवर्स पलायन के कारण श्रमिकों के अभाव होने से कृषि गतिविधियां थम सी गयी। वहीं दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगलूरू, कोलकाता और हैदराबाद जैसे महानगरों में दैनिक कार्यों में सहायता करने वाले रसोईया, डिलीवरी बॉय, चपरासी, गार्ड आदि का अभाव हो गया। रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर और राजमिस्त्री उपलब्ध न होने से निर्माण कार्य की लागत बढ़ी है।
3. पिछड़े राज्यों के लिए गंभीर संकट– औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड, मध्य प्रदेश और ओडिसा में प्रवासियों के लौटने से रोजगार एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराने का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ज्ञातव्य है प्रवासी श्रमिकों की आय देश के जी0डी0पी0 की 6 फीसदी है जिसमें से वे एक तिहाई हिस्सा अपने मूल गांव भेजते थे, वो बन्द होने से राज्यों के समक्ष आर्थिक दबाव बढ़ा है।
4. भारतीय अर्थव्यवस्था का अस्थिर होना– विशेषज्ञों के अनुसार रिवर्स पलायन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 15 वर्ष पीछे ढकेल दिया है।
5. अनैतिक कार्यों में वृद्वि– काम–धन्धा बन्द होने से समाज में चोरी, डकैती, अपहरण, देह व्यापार जैसे अनैतिक कार्य प्रारम्भ हो गए हैं।

रिवर्स पलायन से निपटने की मुख्य चुनौतियां–

1. एक प्रवासी प्रतिदिन 500 से 700 रूपए प्रतिदिन कमाने वाला मनरेगा योजना में 202 रूपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर काम क्यों करेगा ?
2. जिन प्रवासियों को शहरों की सुख–सुविधाएं मन को भा गई हों, वो फिर गांव में क्यों रूकेगा ?
3. क्या प्रभावित राज्य सरकारें इन प्रवासियों को अपने यहां शहरों एवं महानगरो में मिलने वाले नौकरियां एवं सामाजिक सुरक्षा दे पाएगीं ?

उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को गहन मन्थन कर आवश्यक कदम उठाने होगें।

रिवर्स पलायन से उत्पन्न समस्याओं हेतु सुझाव–

1. क्लस्टर आधारित विकास मॉडल अपनाना– इस के अन्तर्गत छोटे–छोटे गांवो को आपस में मिलाकर उनके लिए विकास योजनाएं बनानी चाहिए। इससे राज्य के सीमित संसाधनों का लाभ सभी को समान रूप से मिलेगा।
2. सरकारी विभागों एवं जनता में आपसी सामजंस्य स्थापित करना– राज्य में संचालित विभिन्न रोजपरक योजनाओं एवं जागरूकता कार्यक्रम की सफलता के लिए आपसी सामजंस्य स्थापित करना होगा।
3. सफल उद्यमियों एवं बुद्विजीवियों को साथ लेकर चलना– स्टार्ट अप एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देना होगा एवं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सफल उद्यमियों एवं बुद्विजीवियों को जोड़ना होगा।
4. ब्याज मुक्त लोन देना एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना– प्रभावित किसानो, स्ट्रीट वेण्डर, प्रवासियों एवं दुकानदारों आदि को विशेष योजना के अर्न्तगत ब्याज मुक्त लोन दिया जाए ताकि वो अपना स्वरोजगार कर आजीविका चला सकें।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना हो– ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना की जाए।

रिवर्स पलायन से उत्पन्न समस्याओं हेतु किए गए सरकारी प्रयास– 12 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर अभियान की शुरूआत की घोषणा की, जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज दिया। जो कुल भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत है। इसका प्रमुख उद्देश्य छोटे दुकानदार, प्रवासी श्रमिक, एम0एस0एम0ई0 तथा लघु एवं कुटीर उद्योग को नई संजीवनी देना है ताकि गिरी अर्थवस्था को पुनः संभाला जा सके। उत्तर प्रदेश और बिहार में मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। जन वितरण प्रणाली के तहत उनको निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने 6 राज्यो (बिहार, यू0पी0, एम0पी0, राजस्थान, झारखण्ड और ओडिसा) के 116 जिलों में 25000 से अधिक प्रवासियों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारम्भ किया गया है। साथ ही मनरेगा में अतिरिक्त 40000 करोड़ प्रवासियों के लिए आबंटित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने "मन की बात" कार्यक्रम में बताया कि उनकी सरकार प्रवासी श्रमिकों के रोजगार हेतु प्रवसन आयोग को स्थापित करने पर विचार कर रही है।

निष्कर्ष– कोरोना महामारी के बाद दुनिया कैसी होगी, इसकी कल्पना करना व्यर्थ है। पूर्व में गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक सुधारों के जो प्रयास हुए हैं उनक लिए जरूरी है कि अधिक सावधानी बरती जाए। लॉकडाउन ऐसा भार है जिसे बार–बार उठाया नहीं जा सकता। इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को आपस में सामंजस्य स्थापित कर मिलजुल कर कार्य करने होगें। आई0 एम0 एफ0 की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है "कोरोना संकट अगले दो वर्षों में विश्व की जी0 डी0 पी0 का 9 खरब डॉलर बर्बाद कर देगा। 1930 की आर्थिक महामंदी के बाद ऐसा पहली बार हो सकता है कि विकसित एवं विकासशील देश दोनों ही मंदी के चक्र में फंस जाए।" विभिन्न वैश्विक आर्थिक संस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान नकारात्मक लगा रही हैं। मूडीज ने भारत की रैंकिंग बी0ए0ए0 2 से घटाकर बी0ए0ए0 3 कर दिया है जो सबसे निचली रैकिंग है। कुछ भी हो रिवर्स पलायन की स्थिति उत्तराखण्ड के लिए एक अवसर के रूप में आयी है। पलायन को रोकने के लिए जो काम यहां की सरकारें पिछले 20 वर्षों में नहीं कर पायी, वो कोरोना महामारी ने कर दिखाया। प्रवासी वीरान गांवो को आबाद कर गांव की बंजर भूमि में खेती कर रहे हैं तथा स्थानीय रोजगार अपना कर यहां की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

सन्दर्भ सूची–

1. https://www.gaonconnection.com/badalta-india/this-person-showed-a-way-to-tackle-the-problem-of-migration-in-uttarakhand-48588?infinitescroll=1
2. Economic & Political Weekly, Vol. 55, Issue No. 23, 6 June 2020
3. Tci.cornell.edu/blog/how will reverse migration affect agriculture and what can the government do?
4. www.dristiias.com
5. www.downtoearth.org, 8 Sept. 2020
6. www.economictimes.com
7. आर्थिक समीक्षा 2020–21 वित्त मंत्रालय ।